

बिहार सरकार
योजना एव विकास विभाग

संकल्प

विषय: **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका-2014 की कंडिका 5(ii), 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 में संशोधन।**

“मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना” की संशोधित मार्गदर्शिका-2014 में योजनाओं के चयन का सिद्धान्त के अनुसार प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष दो करोड रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशसा करने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत माननीय विधान परिषद् सदस्य के लिए प्रत्येक वर्ष एक जिला का चयन का प्रावधान संशोधित मार्गदर्शिका-2014 में अंकित है।

विगत दिनों निर्माण सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण विधान मंडल सदस्यों के द्वारा प्रति वर्ष प्रावधानित दो करोड रूपये से विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के क्षेत्रीय सतुलन बनाये रखने में कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष तीन करोड रूपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशसा करने एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत माननीय विधान परिषद् सदस्य के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम दो जिला के चयन करने के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका-2014 की कंडिका 5(ii), 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

- 5(ii)- बिहार विधानसभा से निर्वाचित एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर वित्तीय वर्ष 2018-19 से राज्य के अधिकतम 2(दो) जिलों का चयन किया जा सकता है एवं जिला चयन के साथ जिलावार राशि कर्णाकण की सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर देना होगा। इस कोटि के माननीय सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष के बाद इच्छा के अनुसार जिला परिवर्तन एवं परिवर्तित जिलावार राशि का कर्णाकण किया जा सकता है।
- 7.1- इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान सभा, सदस्य वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशसा करेंगे। परन्तु इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा के सदस्य संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक सीमा के अधीन ही अपनी योजनाओं की अनुशसा करेंगे।
- 7.2- इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान परिषद् सदस्य भी वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशसा कर सकेंगे।
- 8.1- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।
- 8.2- विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रवार वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।
- 8.3- विधान परिषद् के उन निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र राज्य के कई जिलों में विस्तारित होगा उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड रूपये प्रतिवर्ष आवंटन देय होगा। उनसे जिलावार अनुशसा के आलोक में आवंटित राशि का प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा। यदि जिलावार प्रतिशत 15 जून तक प्राप्त नहीं हो पाता है तो निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार विभाजित राशि के अनुरूप आवंटन दिया जायेगा।
- 8.7- माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् जो बिहार विधानसभा से निर्वाचित है अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं, वे वित्तीय वर्ष 2018-19 से राज्य के अधिकतम दो जिलों को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे तथा उन्हें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड रूपये का आवंटन प्रतिवर्ष देय होगा। वे वित्तीय वर्ष के उपरांत चयनित जिलों के

स्थान पर अन्य जिलो का चयन कर सकते है परन्तु यह इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि जिलों में बदलाव की परिस्थिति में पूर्ववर्ती जिलों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के वित्तीय दायित्व की पूर्ति के उपरांत अवशेष राशि ही माननीय सदस्य के द्वारा चयनित जिलों में उनकी अनुशसा के आलोक में हस्तांतरित होगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक. यो03/मु.क्षे.वि.यो.-1/2010-3924 /यो.वि.,पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि: बिहार विधान मण्डल के माननीय सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक. यो03/मु.क्षे.वि.यो.-1/2010-3924 /यो.वि.,पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक: यो03/मु.क्षे.वि.यो.-1/2010-3924 /यो.वि.,पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि: सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक: यो03/मु.क्षे.वि.यो.-1/2010-3924 /यो.वि.,पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक यो03/मु.क्षे.वि.यो.-1/2010-3924 /यो.वि.,पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक: यो03/मु.क्षे.वि.यो.-1/2010-3924 /यो.वि.,पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में प्रकाशनार्थ सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियों विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव